लक्ष्यों तथा आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	निधारित भौतिक लक्ष्य	आबंटित निधियां (केन्द्र + राज्य) (रुपए लाख में)
1. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम		
(1) अखिल भारत	केन्द्र द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है	9025.00
(2) पंजाब	-वही-	43.00
2. जवाहर रोजगार योजना		
(1) अखिल भारत	4288.58 लाख श्रम दिन	2,23,679.48
(2) पंजाब	15.62 लाख श्रम दिन	1089.39
3. सुनिश्चित रोजगार योजना		
(1) अखिल भारत	1161.04 सृजित श्रम दि (उपलब्धि)	77,737.50*
(2) पंजाब	कार्यान्वित नहीं	कार्यान्वित नहीं की गई।

* रिलीज की गई निधियां

Losses in the Power Sector

713. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased state:

(a) the total financial losses in the power sector in the country during the last three years;

(b) the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to prevent such losses in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOCURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI) (a) The losses of the 17 State Elertricity Board, as a whole, without taking into account Rural Electrification Subsidy, as provided in the accounts were Rs. 2893.90 crores, Rs. 3418.74 crores and Rs. 4294.37 crores during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 respectively.

(b) The reasons for the losses of tne SEBs, inter-alia inculde unremunerative tariff including the agricultural tariff, non-conversion of loans into equity, high T&D losses, low level of PLF, high fuel consumption in Thermal Power Stations, etc.

(c) In order to improve the functioning of the SEBs, State Govrnments/SEBs have been advised, from time to time, to undertake measures of rationalisation of tariff, regular payment of ural electrification subsidy, improvement in Plant Load Factor (PLF), installation of Tamper Proff Meters, disconnection of illegal connections etc.

वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में शिकायतें

714. **श्री रामजीलाल:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित वृद्धावस्था पेंशन सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर मिल रही है;

(ख) यदि हां, यह पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी राशि कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस अवधि का ब्यौरा क्या है जिसके भीतर इन शिकायतों का निपटान करके पेंशन प्रदान कर दी जाती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Requirement of Assam in The Power Sector

715. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the requirements of Assam in power sector; and

(b) what are the details of projects initiated/contemplated to meet the requirements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI) (a) The 15th Electric Power Survey project the energy requirement and peak load of Assam to be of the order of 4976 MUs and 986 MW resepctively in 2001-02.

(b) Presently Dhansiri HEP (20 MW) is under execution in the State Sector. In Principle clearance has been accorded to Karbi Langpi HEP (100MW) and Namrub CCPP (120 MW) for execution in the private sector. Assam is also entitled to its share of power from Kathalguri CCGT (291 MW) and Kopili HEP (100 MW) being executed by NEEPCO in the Central Sector.

मध्य प्रदेश में बायोगैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हे

716. **श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1995-96 में और 1996-97 में अब तक मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हे लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इन संयंत्रों और चूल्हों का देश के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, पर्यावरण तथा ऊर्जा-खपत के ढांचे पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपाला चारी): (क) और (ख) जी हां। अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश राज्य सरकार को प्रस्तावों और पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन के आधार पर आवंटित किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं; संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के लिए 18.500 पारिवारिक बायोगैस संयंत्र, 5 विष्ठा आधारित संयंत्र और 2.70 लाख उन्नत चूल्हे तथा वर्ष 1996-97 के लिए 18,000 पारिवारिक बायोगैस संयंत्र, 10 विष्ठा आधारित संयंत्र और 2.35 लाख उन्नत चूल्हे।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 और 1996-97 अक्तूबर, 1996 तक क्रमशः पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों के लिए कुल 2.58 करोड़ रुपये और 4.71 करोड़ रुपये तथा उन्नत चूल्हों के लिए 1.67 करोड़ रुपये और 0.67 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से मंजूर की गई है।

(घ) देश में अब तक लगभग 23.70 लाख पारिवारिक बायोगैस संयंत्र, 1750 सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र और 227 लाख उन्नत चूल्हे लगाए गए हैं जिसके फलस्वरूप वायोमास ईंधन का कुशल उपयोग हो रहा है और प्रतिवर्ष लगभग 185 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर अनुमानित बचत हो रही है, इस प्रकार देश को अन्य लाभों के साथ-साथ पर्यावरण में सुधार हो रहा है।

Management of Off-Shore Oil Fiefids of Andhra Pradesh

717. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether oilfields of the coastal Andhra Pradesh presently under Australian management;